MTNL के पेंशन का टेंशन दूर करेगा PMO

टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारियों की पेंशन पर चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए सचिवों की एक कमेटी को सौंपी गई जिम्मेदारी

जोजी थॉमस फिलिप
नई दिल्ली

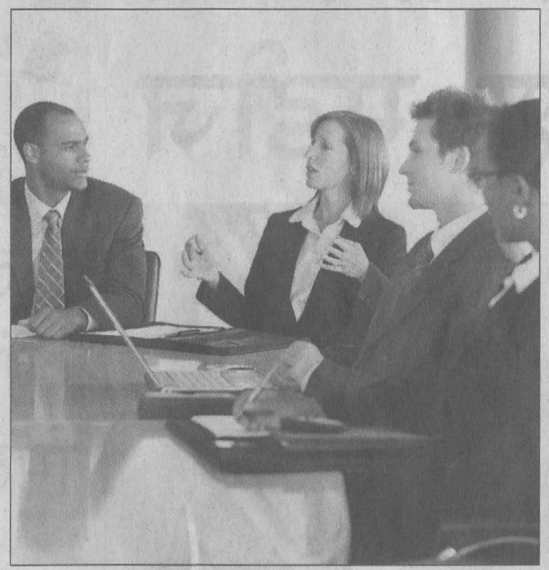

सरकारी टेलीकॉम कंपनी एमटीएनएल के कर्मचारियों की पेंशन को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सचिवों की एक कमेटी को जिम्मेदारी सौंपी है। एमटीएनएल का कहना है कि बढ़ते घाटे की वजह से उसके लिए यह वित्तीय बोझ उठाना मुश्किल हो सकता है।

इस मुद्दे को लेकर बड़ा विवाद खड़ा होने की वजह से पीएमओ को हस्तक्षेप करना पड़ा है। एमटीएनएल को पेंशन के लिए राहत पैकेज देने पर बहुत से विभागों की अलग-अलग राय है। पीएमओ ने कहा है कि सचिवों की कमेटी को इस मुद्दे को सुलझाकर केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सामने संभावित समाधान रखने चाहिए।

दिल्ली और मुंबई में टेलीकॉम सर्विसेज देने वाली एमटीएनएल अपने कर्मचारियों को बीएसएनएल की तुलना में ऊंचे ग्रेड पर वेतन देती है। इसी वजह से एमटीएनएल को पेंशन का भार खुद उठाना पड़ता है। दूसरी ओर बीएसएनएल के कर्मचारियों के पेंशन बिल के भुगतान की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है।

कुछ सरकारी विभागों को आशंका है कि अगर केन्द्र एमटीएनएल के पेंशन बिल के कुछ हिस्से का भुगतान करता है तो इससे बीएसएनएल के 3,00,000 कर्मचारी दोनों कंपनियों में वेतन को लेकर समानता की मांग कर सकते हैं। पेंशन और पेंशनभोगियों के कल्याण विभाग का कहना है कि अगर दोनों कंपनियों में कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन को एम समान कर दिया जाए तो उससे भी परेशानी हो सकती है क्योंकि इसके बाद इसी सेक्टर की अन्य पीएसयू से भी इस तरह की मांग उठ सकती है। लेकिन एक्सपेंडिचर विभाग का कहना है कि वह इस राय से सहमत नहीं है। मार्च, 2010 में समाप्त हुए वित्त वर्ष में एमटीएनएल ने 2,514 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया था। कंपनी का कहना था कि इस नुकसान की एक बड़ी वजह रिटायरमेंट लाभ का एकमुश्त भुगतान है। जून, 2010 में समाप्त हुए इस वित्त वर्ष के पहले तीन महीनों में कंपनी का नुकसान 451.4 करोड़ रुपए था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 10 गुना अधिक है। कंपनी का कहना है कि वेतन के बढ़ते बोझ और रिटायरमेंट लाभ के लिए वित्तीय प्रावधान करने से उसका प्रदर्शन गिर रहा है। एमटीएनएल में सरकार की 56 फीसदी हिस्सेदारी है।

कंपनी ने अपनी आमदनी और मुनाफे में लगातार हो रही कमी को रोकने के लिए केन्द्र से कर्मचारियों की संख्या में दो-तिहाई की कमी करने की अनुमति मांगी है। एमटीएनएल का कहना है कि आने वाले समय में पेंशन का भार और बढ़ेगा और टेलीकॉम सेक्टर में निजी कंपनियों से मिल रही कड़ी प्रतियोगिता को देखते हुए उसके लिए इसे वहन करना असंभव हो जाएगा टेलीकॉम विभाग ने एमटीएनएल की मौजूदा स्थिति के लिए खुद कंपनी को ही जिम्मेदार बताया है।

पेंशन का भार खुद उठाती है कंपनी

- एमटीएनएल अपने कर्मचारियों को बीएसएनएल की तुलना में ऊंचे ग्रेड पर वेतन देती है। इसी वजह से टेलीकॉम कंपनी को पेंशन का भार खुद उठाना पड़ता है
- मुद्दे पर विवाद खड़ा होने की वजह से पीएमओ को हस्तक्षेप करना पड़ा। एमटीएनएल को पेंशन के लिए राहत पैकेज देने पर बहुत से विभागों की अलग-अलग राय है
- एमटीएनएल में केंद्र की 56 फीसदी हिस्सेदारी है। आमदनी और मुनाफे में कमी को रोकने के लिए कंपनी ने कर्मचारियों की दो-तिहाई संख्या घटाने की मांग की है

PMO सुलझाएगा MTNL कर्मियों का पेंशन विवाद

सरकारी टेलीकॉम कंपनी एमटीएनएल के कर्मचारियों की पेंशन को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सचिवों की एक कमेटी को जिम्मेदारी सौंपी है। एमटीएनएल का कहना है कि बढ़ते घाटे की वजह से उसके लिए यह वित्तीय बोझ उठाना मुश्किल हो सकता है। इस मुद्दे को लेकर बड़ा विवाद खड़ा होने की वजह से पीएमओ को हस्तक्षेप करना पड़ा है। एमटीएनएल को पेंशन के लिए राहत पैकेज देने पर बहुत से विभागों की अलग-अलग राय है।

कंपनी न्यूज: पेज 3